कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून –248001

Email ID- ceo_uttaranchal@eci.gov.in
election09@gmail.com

फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्या– 3137/XXV – 05 /2021 **देहरादून :** **दिनांक 27 मई, 2022**

सेवामें,

MOST IMPORTANT
URGENT

समस्त अध्यक्ष/सचिव,
पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल
उत्तराखण्ड (संलग्न सूची के अनुसार–41)

द्वारा :– सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी,
चमोली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार,
पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा एवं नैनीताल।

विषयः– लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–29क, 29ख, एवं 29ग तथा निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 के नियम–85ख एवं आयोग द्वारा तद् विषयक समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में वित्तीय वर्ष–2017–18 से 2021–22 तक अंशदान, आय–व्ययक–ऑडिट रिपोर्ट एवं विभिन्न निर्वाचनों में व्यय विवरण की सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–56/pol.parties/2021/ PPS-III दिनांक 25 मई, 2022 के साथ आयोग के आदेश संख्या– 56/pol.parties/2021/ PPS-III (Part)/Conf- दिनांक 25 मई, 2022 **(प्रति संलग्न पृष्ठ–19 से 27)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमे आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दलों से उक्त आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिन के भीतर दल के मुख्यालय के पते की पुष्टि/परिवर्तन (यदि कोई हो) के साथ ही अंशदान, आय–व्ययक–ऑडिट रिपोर्ट एवं विभिन्न निर्वाचनों में व्यय विवरण की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

2– उपरोक्त के संबंध में आपका ध्यान स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रेषित इस कार्यालय के पत्र संख्या–3083/XXV-05/2021 दिनांक 23 मई, 2022 (प्रति पुनः संलग्न पृष्ठ संख्या–01 से 18) की ओर आकृष्ठ करते हुए अवगत कराना है कि इस कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 23 मई, 2022 के साथ संलग्न निम्न प्रारूपों पर विभिन्न सूचनाएं दिनांक 25 जून, 2022 तक उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी हैः–

- **वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में आपके दल को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंशदान की सूचना संलग्न Annexure-A पर,**
- **वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में वर्ष वार आय–व्ययक/ऑडिट रिपोर्ट की सूचना (सीए द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट सहित)** Annexure-B **पर,**
- **विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 से वर्ष 2022 में वर्तमान तक विभिन्न विधान सभा/लोक सभा सामान्य/उप निर्वाचनों में आपके दल द्वारा व्यय की गयी धनराशि की सूचना संलग्न** Annexure-C **पर,**

- वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में राजनैतिक दल को रू0 20,000/– से अधिक धनराशि के प्राप्त अंशदानों का स्पष्ट विवरण प्रारूप–24क (24A) पर।
- यह भी स्पष्ट करना है कि यदि किसी राजनैतिक दल के सम्बन्ध में उल्लिखित किसी वित्तीय वर्ष अथवा सभी वित्तीय वर्षों की कोई सूचना शून्य भी हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्षवार संलग्न प्रारूपों पर वांछित सूचना शून्य अंकित करते हुए अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों से अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाय, ताकि सूचना समय पर आयोग को भी भेजी जा सके ।
- किसी राजनैतिक दल से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत उल्लिखित प्रारूपों पर वित्तीय वर्षवार सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में तद्नुसार आयोग को सूचित किया जायेगा और तदुपरान्त आयोग द्वारा दल की मान्यता के संबंध में विचार किया जा सकता है।
- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा–29क, 29ख एवं 29ग के उद्धरण की प्रति भी सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न प्रेषित है। (पृष्ठ–28 से 33 तक)
- कृपया पूर्ण रूप से भरे हुए Annexure-A, B, C and प्रारूप–24क (24A) पर राजनैतिक दल के अधिकृत प्रतिनिधि/पदाधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रतिनिधि/पदाधिकारी का पूरा नाम, पदनाम, पूरा पता एवं मोबाइल नम्बर अंकित करने के साथ–साथ दल का पेनकार्ड नम्बर एवं बैंक खाता विवरण अनिवार्यतः उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- उत्तराखण्ड राज्य में पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दलों की संलग्न सूची में जिन दलों के द्वारा विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017, लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 एवं विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 में निर्वाचन लड़ा गया है उनके सम्मुख आवश्यक टिप्पणी अंकित की गयी है।

अतः अनुरोध है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा–29क, 29ख एवं 29ग, निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 एवं आयोग द्वारा समय–समय पर तद्विषयक जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की वित्तीय वर्षवार राजनैतिक दल को प्राप्त अंशदान, आय–व्ययक ऑडिट रिपोर्ट, विभिन्न निर्वाचनों में व्यय का विवरण तथा रू0 20,000/– से अधिक धनराशि के अंशदान की प्राप्ति के सम्बन्ध में सुस्पष्ट विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूपों पर बिलम्बतम दिनांक 25 जून 2022 तक ई–मेल आईडी ceo_uttaranchal@eci.gov.in या election09@gmail.com के द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी/सहायता के लिए सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास के मोबाईल नम्बर 9412026375 पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(सौजन्या)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
उत्तराखण्ड।

B

रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

अधिसूचना में क्रम सं0	क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल / मुख्यालय का पता	विधान सभा निर्वाचन–2017 में चुनाव लड़ा गया (हाँ / नहीं)	लोक सभा निर्वाचन–2019 में चुनाव लड़ा गया (हाँ / नहीं)	विधान सभा निर्वाचन–2022 में चुनाव लड़ा गया (हाँ / नहीं)
1	2	3	4	5	6
453	1.	भारत कौमी दल ग्राम -लाठ्ठरदेवा हूण, पो0 झबरेडा, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	नहीं
466	2.	भारत परिवार पार्टी भारत ह्रदय आश्रम, मौ0 कड़च्छ ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407	नहीं	नहीं	नहीं
510	3.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल बंसल गांव, पो. ऑ. - धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला - अल्मोडा (उत्तराखण्ड) ।	नहीं	नहीं	नहीं
536	4.	भारतीय जनक्रांति पार्टी 12/17, चक्खुवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
552	5.	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी 77/129, भगत सिहँ कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
585	6.	भारतीय सम्राट सुभाष सेना ग्राम - अजीतपुर, पो0 - कनखल,लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408	नहीं	नहीं	नहीं
597	7.	भारतीय शक्ति सेना शक्ति सेना भवन, बैरियर नं0 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद, हरिद्वार - 249 402 उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
620	8.	भारतीय अंत्योदय पार्टी 8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171	नहीं	नहीं	नहीं
646	9.	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी एकता विहार, लेन नं. -1,ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पी0ओ0 -कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001 ।	नहीं	नहीं	नहीं
767	10.	भारतीय सर्वोदय पार्टी 152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।	हाँ	हाँ	नहीं
770	11.	भारतीय सेवक पार्टी उत्तराखण्ड ग्रमिण बैंक के नजदीक, बुग्गावाला (मेन मार्केट) हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन–247662	नहीं	नहीं	नहीं
789	12.	भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी मकान न0 63 रामपुर रोड़ मानपुर उत्तर हल्द्वानी नैनीताल पिन–263139	नहीं	नहीं	नहीं
962	13.	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट शाही निवास चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं

(C)

977	14.	हमारी जनमंच पार्टी 1/12, नया चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	नहीं
1538	15.	मैदानी क्रान्ति दल मुख्यालय - मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।	नहीं	नहीं	नहीं
1783	16.	न्याय धर्मसभा पार्टी प्रगति विहार जगजीतपुर हरिद्वार पिन 24908	नहीं	नहीं	हाँ
1798	17.	पहाड़ी पार्टी ग्रा0ततली बागी पट्टी सारज्यूला पो0 भगीरथपुरम विकास खण्ड चम्बा जिला टिहरी पिन 249145	नहीं	नहीं	नहीं
1829	18.	पीपुल्स पार्टी ए-23, सुभाष नगर, रूड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड	हाँ	नहीं	नहीं
1865	19.	प्रगतिशील लोक मंच ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा, पो0 ओ0 - अर्जुनपुर (हल्द्वानी), जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड ।	नहीं	हाँ	नहीं
1890	20.	प्रजामंडल पार्टी बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गढवाल, उत्तराखण्ड - 246174	हाँ	नहीं	नहीं
1897	21.	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं
2017	22.	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।	हाँ	नहीं	हाँ
2059	23.	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी 62, सिविल लाईन्स , रूड़की, जनपद - हरिद्वार,उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
2081	24.	राष्ट्रीय जन सहाय दल 112, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	नहीं
2249	25.	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी 124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	हाँ
2318	26.	सैनिक समाज पार्टी 317– शिवा डिस्पोजल कैम्प्लेक्स संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड़ चन्द्रभागा आर्दश ग्राम ऋषिकेश पिन–249201	हाँ	नहीं	हाँ
2405	27.	सर्व विकास पार्टी गाँव - प्रतीत नगर, एन0 एच0 - 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205	हाँ	हाँ	नहीं
2527	28.	सुराज सेवा दल ग्राम - रामड़ी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं

(D)

2694	29.	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001	नहीं	नहीं	नहीं
2695	30.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	हाँ	हाँ
2696	31.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रिटिक) 85/ 12 – बी, नाश विला रोड़, देहरादून – 248001, (उत्तराखंण्ड)।	हाँ	हाँ	हाँ
2697	32.	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला – चमोली, उत्तराखण्ड ।	हाँ	हाँ	हाँ
2698	33.	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी 13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोजेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।	नहीं	हाँ	नहीं
2699	34.	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा मकान नं0 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट–मोथरोंवाला, विकासखण्ड–रायपुर, जिला–देहरादून, (उत्तराखण्ड)	हाँ	नहीं	हाँ
2702	35.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी 53 – के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
2693	36.	उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी 18– एफ, सेक्टर बी0 निकट सी0 ब्लॉक टाईप 2 नई टिहरी	नहीं	नहीं	हाँ
2692	37.	उत्तराखण्ड जनता पार्टी प्लाट न0–6 प्रकाश इनक्लेव, शिमला रोड़, सेवला कला, देहरादून उत्तराखण्ड–248001	नहीं	नहीं	हाँ
2877	38.	भारत एकता मिशन पार्टी 171/123, आराघर, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं
11-03-2022	39.	राज्य सवराज पार्टी 931,इन्दरा नगर, देहरादून उत्तराखण्ड।	नहीं	नहीं	नहीं
2805	40.	जनता कैबिनेट पार्टी, 16/ A (16/1) , लेटान रोड़ सुभाष रोड देहरादून न्यू नगर निगम, न0 184/4, पिन 248001 उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं
2875	41.	भारतीय राष्ट्रीय एकता दल, 10/10, मोहल्ला कैटवाड़ा, निय अम्बेडकर चौक, ज्वालापुर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249407	नहीं	नहीं	नहीं

नोटः– 1–विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 में निर्वाचन लड़ने वाले दलों की संख्या–14
2–लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में निर्वाचन लड़ने वाले दलों की संख्या–07
3–विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 में निर्वाचन लड़ने वाले दलों की संख्या–10

E

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001

फोन नo (0135) – 2713760, 2713551
फैक्स नo (0135) – 2713724

E-Mail- election09@gmail.com ceo_uttaranchal@eci.gov.in

संख्याः 3083 /XXV–05/2021 देहरादूनः दिनांक 23 मई 2022.

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/सचिव,
पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल (संलग्न सूची के अनुसार),
उत्तराखण्ड।

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18, से 2021–22 तक की अंशदान, आय–व्ययक–ऑडिट रिपोर्ट, विभिन्न निर्वाचनों में व्यय विवरण की सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक मुझे यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम/निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 में नियत प्राविधानों के अनुसरण में राजनैतिक दलों कों प्राप्त अंशदान, आय–व्ययक एवं निर्वाचन व्ययों में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्राप्त अंशदान, आय–व्ययक की ऑडिट रिपोर्ट एवं विभिन्न निर्वाचनों में व्यय की गयी धनराशि आदि का विवरण आयोग को प्रस्तुत किये जाने का प्राविधान है। निहित प्राविधानों के अनुसरण में ही वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की आपके दल को प्राप्त अंशदान, आय–व्ययक ऑडिट रिपोर्ट तथा विभिन्न निर्वाचनों के प्रयोजन हेतु दल द्वारा किये गये निर्वाचन व्ययों के विवरण की निम्नानुसार संलग्न प्रारूपों पर तत्काल आवश्यकता हैः–

1	Form-24A	निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम–85ख में नियत प्राविधानों के अनुसार राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या राजनैतिक दल द्वारा इस निमित अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय कर अधिनियम–1961(1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से पूर्व प्रारूप 24क में निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत किया जाना।
2	Annexure-A	संविधान के अनुच्छेद 324 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तद्विषयक जारी दिशा–निर्देशों के अनुसरण में राजनैतिक दलों के आय–व्यय के सम्बन्ध में पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अंशदान, ऑडिट रिपोर्ट तथा विभिन्न निर्वाचनों में व्यय की गयी धनराशि का विवरण उपलब्ध कराना। (Annexure-A पर वित्तीय वर्षवार प्राप्त अंशदान, Annexure-B पर वित्तीय वर्षवार आय–व्ययक एवं ऑडिट रिपोर्ट तथा Annexure-C पर विभिन्न निर्वाचनों में दल द्वारा किये गये गये व्यय का वितरण।)
3	Annexure-B	
4	Annexure-C	

2– उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या–972 दिनांक 16 जून 2021 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–76/PPEMS/Transparency/2013 दिनांक 29 अगस्त 2014, पत्र संख्या– 76/PPEMS/Transparency/2014 दिनांक 14 अक्टूबर 2014 तथा पत्र संख्या–76/PPEMS/Transparency/2013 दिनांक 19 नवम्बर 2014 की प्रति पुनः सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित हैं।

F/RTI-Un Registerd Party Uttarakhand

(1)

3– वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2021–22 में आपके दल को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अंशदान की सूचना संलग्न Annexure-A पर,

- उल्लिखित वित्तीय वर्षों में वर्ष वार आय–व्ययक/ऑडिट रिपोर्ट की सूचना (सीए द्वारा ऑडिटेड बैलेंस शीट सहित) Annexure-B पर,
- विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 से वर्ष 2022 में वर्तमान तक विभिन्न विधान सभा/लोक सभा सामान्य/उप निर्वाचनों में राजनैतिक दल द्वारा व्यय की गयी धनराशि की सूचना संलग्न Annexure-C पर,
- उल्लिखित वित्तीय वर्षों में राजनैतिक दल को प्रारूप–24क (24A) पर रू0 20,000/– से अधिक धनराशि के प्राप्त अंशदानों का स्पष्ट विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
- यह भी स्पष्ट करना है कि यदि किसी राजनैतिक दल के सम्बन्ध में उल्लिखित किसी वित्तीय वर्ष अथवा सभी वित्तीय वर्षों की कोई सूचना शून्य भी हो तो ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्षवार संलग्न प्रारूपों पर वांछित सूचना शून्य अंकित करते हुए अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षरों से अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जाय, ताकि सूचना समय पर आयोग को भी भेजी जा सके ।
- किसी राजनैतिक दल से निर्धारित तिथि के अन्तर्गत उल्लिखित प्रारूपों पर वित्तीय वर्षवार सूचना प्राप्त न होने की स्थिति में तद्नुसार आयोग को सूचित कर लिया जायेगा और तदुपरान्त आयोग द्वारा दल की मान्यता बनाये रखने अथवा समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है, जिसके लिए सम्बन्धित दल स्वयं उत्तरदायी होगा।
- यदि किसी राजनैतिक दल का भारत निर्वाचन आयोग में उल्लिखित वित्तीय वर्षों में से किसी वित्तीय वर्ष के पश्चात ही पंजीकरण हुआ हो तो ऐसे राजनैतिक दल पंजीकरण तिथि के पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों की वांछित सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगें।

अतः अनुरोध है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, निर्वाचनों का संचालन नियम–1961 एवं आयोग द्वारा समय–समय पर जारी तद्विषयक दिशा–निर्देशों के अनुसरण में उपरोक्तानुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 से 2021–22 तक की वित्तीय वर्षवार राजनैतिक दल को प्राप्त अंशदान, आय–व्ययक ऑडिट रिपोर्ट, विभिन्न निर्वाचनों में व्यय का विवरण तथा रू0 20,000/– की धनराशि से अधिक अंशदान की प्राप्ति के सम्बन्ध में सुस्पष्ट विवरण संलग्न निर्धारित प्रारूपों पर बिलम्बतम दिनांक 25 जून 2022 तक पत्र के शीर्ष में अंकित ई–मेल आईडी पर ई–मेल के द्वारा अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

F/RTI-Un Registerd Party Uttarakhand

ANNEXURE-A

पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (Registered Unrecognised Political Parties) द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए गए अंशदान की सूचना।

वित्तीय वर्ष	संस्था/व्यक्ति का नाम जिससे/जिनसे अंशदान प्राप्त हुआ है	अंशदान की प्राप्ति का दिनांक	अंशदान की धनराशि	अंशदान प्राप्ति का माध्यम (नकद/चैक/बैंक ड्राफ्ट/बैंक खाता द्वारा)	दल का बैंक खाता नम्बर एवं बैंक का नाम जिससे लेन–देन किया जाता है
1	2	3	4	5	6
2017–18 (01.4.2017 से 31.03.2018 तक)					
2018–19 (01.4.2018 से 31.03.2019 तक)					
2019–20 (01.4.2019 से 31.03.2020 तक)					
2020–21 (01.4.2020 से 31.03.2021 तक)					
2021–22 (01.4.2021 से 31.03.2022 तक)					

दल की मुहर...

ई–मेल आई.डी.....

दल के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर....
प्रतिनिधि का पूरा नाम.....
मोबाइल नम्बर..
दल का नाम ....
पूरा पता...

(3)

ANNEXURE-B

पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (Registered Unrecognised Political Parties) के वार्षिक आय–व्यय विवरण, लेखा–परीक्षा रिपोर्ट की सूचना।

वित्तीय वर्ष	कुल आय (धनराशि में)	कुल व्यय (धनराशि में)	अंशदान की धनराशि	वित्तीय वर्ष की आय–व्यय को CA द्वारा Audit करवाया गया (हाँ/नहीं)	कृपया CA द्वारा Audited Report अनिवार्यतः संलग्न करें।
1	2	3	4	5	6
2017–18 (01.4.2017 से 31.03.2018 तक)					
2018–19 (01.4.2018 से 31.03.2019 तक)					
2019–20 (01.4.2019 से 31.03.2020 तक)					
2020–21 (01.4.2020 से 31.03.2021 तक)					
2021–22 (01.4.2021 से 31.03.2022 तक)					

कृपया वर्षवार CA द्वारा Audited Report इस सूचना के साथ अनिवार्यतः संलग्न करें।

दल की मुहर...

ई–मेल आई.डी.....

दल के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर....

प्रतिनिधि का पूरा नाम.....

मोबाइल नम्बर..

दल का नाम ....

पूरा पता...

ANNEXURE-C

पंजीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल (Registered Unrecognised Political Parties) द्वारा विभिन्न निर्वाचनों में किए गए निर्वाचन व्ययों का विवरण।

निर्वाचन का नाम	क्या दल द्वारा कॉलम–1 में अंकित किसी सामान्य/उप निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े किए गए (हाँ/नहीं)	यदि हाँ तो कुल कितनी विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में दल के प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन लड़ा गया	कॉलम–3 के अनुसार निर्वाचन लड़े जाने के फलस्वरूप संबंधित निर्वाचन के लिए केवल दल द्वारा व्यय की गयी कुल धनराशि
1	2	3	4
1.विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017			
2.लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019			
3.विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022			
4.विधान सभा उप निर्वाचन, यदि कोई हो–2017 से अब तक			
5.लोक सभा उप निर्वाचन, यदि कोई हो–2017 से अब तक			

नोट–कॉलम–4 में केवल दल द्वारा व्यय की गयी धनराशि ही अंकित की जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा व्यक्तिगत रूप से व्यय की गयी धनराशि इसमें सम्मिलित नहीं की जायेगी।

दल की मुहर...

ई–मेल आई.डी.....

दल के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर....
प्रतिनिधि का पूरा नाम.....
मोबाइल नम्बर..
दल का नाम ....
पूरा पता...

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules and Order)

[1][FORM 24A
(*See* rule 85B)

[This form should be filed with the Election Commission before the due date for furnishing a return of the Political Party's income of the concerned financial year under section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and a certificate to this effect should be attached with the Income-tax return to claim exemption under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).]

1. Name of Political Party:

2. Status of the Political Party:
(recognised/unrecognised)

3. Address of the headquarters of the Political Party:

4. Date of registration of Political Party with Election Commission:

5. Permanent Account Number (PAN) and Income-tax Ward/Circle where return of the political party is filed:_____

6. Details of the contributions received, in excess of rupees twenty thousand, during the Financial Year:20 – . –20 .

Serial number	Name and complete address of the contributing person/company	PAN (if any_ and Income-Tax Ward/Circle	Amount of contribution (Rs.)	Mode of contribution *(cheque/demand draft/cash)	Remarks

*In case of payment by cheque/demand draft, indicate name of the bank and branch of the bank on which the cheque/demand draft has been drawn.

7. In case the contributor is a company, whether the conditions laid down under section 293A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) have been complied with (A copy of the certificate to this obtained from the company should be attached).

Verification

I,_____(full name in Block letters), son/daughter of _____solemnly declare that to the best of my knowledge and belief, the information given in this Form is correct, complete and truly stated.

I further declare that I am verifying this form in my capacity as _____on behalf of the Political Party above named and I am also competent to do so.

(Signature and name of the Treasurer/Authorised person)]

Date:_____
Place:_____

1. Ins. by Notifn. No. S.O. 1283(E), dated the 10th November, 2003.

(6)

प्रारूप–24क

(नियम–85ख देखिए)

यह प्ररूप आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन संबंधित वित्तीय वर्ष के दौरान वर्ष के दौरान राजनैतिक दल की आय की विवरणी प्रसतुत करने के लिए नियत तारीख से पूर्व निर्वाचन आयोग के समक्ष फाइल किया जाना चाहिए और इस आशय का एक प्रमाणपत्र आय–कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अधीन छूट का दावा करने के लिए आय–कर विवरणी के साथ संलग्न किया जाना चाहिए।

1– राजनैतिक दल का नामः–

2– राजनैतिक दल की प्रास्थिति (मान्यताप्राप्त/अमान्यताप्राप्त):–

3– राजनैतिक दल के मुख्यालय का पताः–

4– निर्वाचन आयोग के पास राजनैतिक दल के रजिस्ट्रीकरण की तारीखः

5– स्थायी खाता स. (पेन) और वह आय–कर वार्ड/सर्किल जहां राजनैतिक दल की विवरणी फाईल की जानी है.....

6– वित्तीय वर्ष 20..... –20..... के दौरान प्राप्त ऐसे अभिदायों के जो बीस हजार से अधिक है, ब्यौरे–

क्रम सं.	अभिदात्री व्यक्ति/कंपनी का नाम और पूरा पता	पेन (यदि कोई हो) और आय–कर वार्ड/सर्किल	अभिदाय की रकम	अभिदाय की रीति। (चैक/मांगदेय ड्राफ्ट/नगद)	टिप्पणियां

चैक/मांगदेय ड्राफ्ट द्वारा संदाय की दशा में, उस बैंक या बैंक की शाखा नाम जिस पर चैक/मांगदेय ड्राफ्ट लिया गया है।

6. यदि अभिदायी एक कंपनी है तो क्या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 239क के अधीन अधिकथित शर्तों का अनुपालन किया गया है (कंपनी से अभिप्राप्त इस आशय के प्रमाणपत्र की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।)

7.

सत्यापन

मैं.....(स्पष्ट अक्षरों में पूरा नाम) पुत्र/पुत्री..... .....सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई जानकारी ठीक, पूर्ण और सही तौर पर बताई गई है।

मैं यह घोषणा करता हूं कि मैं, ऊपर नामित राजनैतिक दल की ओर से..... .....की अपनी हैसियत में इस प्ररूप को सत्यापित कर रहा हूं और मैं ऐसा करने के लिए सक्षम भी हूं।

(कोषाध्यक्ष/प्राधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर और नाम)

तारीखः.....

स्थानः–.....

3/8/21

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Qksu u0 ¼0135½ & 2713760] 2713551
QSDI u0 ¼0135½ & 2713724

संख्याः 472 /XXV–1(1–4)/2008 देहरादूनः दिनांक 16 जून 2021.

सेवा में,

समस्त अध्यक्ष/सचिव,
रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल (संलग्न सूची के अनुसार)
उत्तराखण्ड।

विषयः **वित्तीय वर्ष 2020–21 आडिट रिपोर्ट, कन्ट्रीव्यूशन रिपोर्ट एवं लोक सभा निर्वाचन–2019 एव उप निर्वाचनों में निर्वाचन व्यय लेखा रिपोर्ट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 की अंशदान रिपोर्ट (Anual Contribution Report), वार्षिक लेखा परीक्षित लेखों (Anual Audit Report) एवं विभिन्न निर्वाचनों में निर्वाचन व्यय लेखा (election expenditure Statement) उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है। समस्त रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों द्वारा निम्न विवरणानुसार लेखे इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने अनिवार्य हैं–

1– अंशदान रिपोर्ट (Anual Contribution Report), समस्त दलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

2– वार्षिक लेखा परीक्षित लेखा (Anual Audit Report) समस्त दलों द्वारा उपलब्ध करायी जानी अपेक्षित है।

3– निर्वाचन व्यय लेखा (Accounting election expenditure Report) केवल उन रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों द्वारा जिनके द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019, 44–पिथौरागढ़, विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन–2019 एवं 49–सल्ट विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन–2021 में उम्मीदवार खड़े किये गये थे। प्रत्येक निर्वाचन से सम्बन्धित पृथक–पृथक विवरण उपलब्ध कराया जाना है।

2– सुलभ संदर्भ हेतु भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–76/PPEMS/Transparency/2013 दिनांक 29 अगस्त 2014, पत्र संख्या– 76/PPEMS/Transparency/2014 दिनांक 14 अक्टूबर 2014 एवं पत्र के साथ संलग्न–Annexure-A,B & C तथा पत्र संख्या–76/PPEMS/Transparency/2013 दिनांक 19 नवम्बर 2014 की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त के सम्बन्ध में मुझे अनुरोध सहित यह कहने के निदेश प्राप्त हुए हैं कि कृपया उपरोक्तानुसार अंशदान, परीक्षित लेखा, एवं निर्वाचन व्यय लेखें का विवरण दिनांक 22 जून 2021 तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

(8)

Annexure- F4

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.76/PPEMS/Transparency/2013 Dated: 29th August, 2014

To

1. The President/General Secretary of all Political parties.
2. The Treasurer of all Political parties.

Subject: Guidelines on transparency and accountability in party funds and election expenditure matter – regarding.

Sir/Madam,

Under Article 324 of the Constitution, Election Commission of India is vested with the responsibility to conduct free and fair elections. Concerns have been expressed in various quarters that money power is disturbing the level playing field and vitiating the purity of elections. To curb the abuse of money power during elections, the Election Commission has issued several instructions in the past to the candidates and political parties from time to time.

2. It is desirable for the political parties to observe transparency and accountability in respect of funds raised and expenditure incurred, both during elections and in other times. Further, in the interest of conduct of free and fair elections it is necessary and expedient to provide guidelines for bringing transparency and accountability with regard to fund of political parties.

3. In order to formulate the guidelines, the Commission sought comment/suggestions/inputs from all recognized political parties. While most of these parties supported the issue of transparency guidelines, some other had a different view. Having regard to the suggestions received from the political parties and in the interest of purity of election process, the Commission hereby issues the following guidelines under Article 324 of the Constitution, to bring transparency and accountability in funding of political parties: -

   (i) Provision (a) to Section 13A of Income Tax Act 1961, inter-alia, provides that political party shall keep and maintain such books of accounts and other documents as would enable proper deduction of its income there from. Accordingly, it is required that (a) the treasurer of the political party or such person as authorized by the party, besides ensuring maintenance of the accounts at all Sate and lower levels, shall maintain consolidated accounts at the central party Head Quarters as required under the aforesaid provision, (b) the accounts so maintained by him/her shall conform to the guidance note on Accounting and Auditing of political parties, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and (c) the Annual Accounts shall be audited and certified by the qualified practicing Chartered Accountants.

   (ii) The Commission has amended the requirements for registration of a new political party w.e.f. 8th

(9)

October 2010, which inter-alia, require a party to submit a copy of its audited annual accounts. Accordingly, in order to bring uniformity, all political parties shall submit to the Commission or to such authority as mentioned in para (vi) below, a copy of the audited Annual Accounts with Auditor's report for each financial year, before 31st October of each year.

(iii) The provisions of Section 80GGB and 80GGC of I.T. Act 1961, inter-alia, state that no deduction shall be allowed on the contributions made in cash by any person or company to a political party. Accordingly, the political party shall maintain name and address of all such individuals, companies or entities making donation to it, excepting petty sums, donated by the public only during its public rallies. Further, any amount/donation received in cash, shall be duly accounted in relevant account books and deposited in the Party's bank account within a week of its receipt. However, the Party can retain a reasonable amount required for day to day functioning of the Party and for defraying the cash expenses.

(iv) Section 40A(3) of Income Tax Act, 1961, provides that all payments exceeding Rs.20,000/-* by any business entity to a person in a day are required to be made by account payee cheque/draft, except the exempted category as provided in Rule 6 DD of Income Tax Rules, 1962. Similarly, if a party is incurring any expenditure, it shall ensure that no payment in excess of Rs.20,000/-* is made in a day to any person or company or entity in cash, except where (a) the payment is made in a village or town, which is not served by a bank; or (b) the payment is made to any employee or party functionary towards salary, pension or for reimbursement of his expenses; or (c) cash payment is required under any statute.

(v) Section 77(3) of the R.P. Act, 1951 provides for a ceiling of election expenditure for a candidate. Therefore, if the party desires to provide any financial assistance to its candidates for their election expenses, such assistance shall not exceed the prescribed ceiling. Any payment in this regard by the party shall be made only through crossed account payee cheque or draft or through bank account transfer and not in cash.

(vi) While the recognized political parties shall file all reports, namely, the contribution reports in Form 24A, the audited Annual Accounts as certified by the Chartered Accountants, referred to in para 3 (i) above, and the Election Expenditure Statements, with the Election Commission of India, the unrecognized parties shall file the same with the Chief Electoral Officer (CEO) of the respective states (i.e. the state where the party Head Quarters is situated) in the prescribed time and manner.

4. The above guidelines shall apply to all political parties with effect from 1st October 2014.

Yours faithfully,

Sd/-

(MALAY MALLICK)

UNDER SECRETARY

(10)

Copy to:

1. All CEOs with request to bring it to the notice of all political parties of their respective states.
2. The Chairman, Central Board of Direct Taxes, North Block, New Delhi for making relevant rules for the political parties.
3. The President, Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, Post Box No.7100, New Delhi – 110022, for incorporating the points in the Guidance note on political parties.

*Note:- Please refer Annexure-E11 & E12

(11)

Annexure –F5

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi – 110001

No.76/PPEMS/Transparency/2014

Dated: 14th October, 2014

To

The Chief Electoral Officers of
All States and UT's.

Subject: Guidelines on transparency and accountability in party funds and election expenditure - submission of reports by unrecognized political parties – regarding.

Sir/Madam,

I am directed to refer the Commission's letter of even No. dated 29th August, 2014 on the subject cited and to state the recognized political parties shall file all reports, namely, (a) the contribution reports in Form 24A, (b) the Audited Annual Accounts, with Auditor report and (c) the Election Expenditure Statements, with the Election Commission of India and the unrecognized parties shall file the same with the Chief Electoral Officers (CEO) of the respective states (i.e. the state where the party Head Quarters is situated) in the prescribed time and manner. The above mentioned guidelines are applicable to all political parties with effect from 1st October, 2014. (Copy enclosed)

2. In view of the above I am directed to request you to bring it to the notice of all such unrecognized political parties having their Head Quarters/official address for correspondence in the state, as per the Commission's Symbol Order notification, to submit the requisite reports in the office of the CEO. (A copy of the Commission's Symbol Order Notification dated 10.03.2014, amendment notification dated 16.09.2014 and letter No. 56/2014/PPS-II dated 26.09.14 are enclosed herewith for ready reference).

3. On receipt of the reports from the State level unrecognized political parties, the following procedure shall be followed by CEO office:

   (i) Scanned copies of the contribution reports, Annual audited accounts and Statements of election expenditure shall be uploaded on the websites of CEOs of the respective states, within 3 days of receipt of the same for viewing by the public. This should be done under the heading "Reports and Accounts statements of State level Political parties", with links from "current news."

   (ii) The list of reports/statements filed by the unrecognized political parties shall be compiled and uploaded on the CEO's website within 24 hrs of the due date, as per proforma enclosed herewith (Annexure- A, B, C). The list shall be periodically updated by the CEO office, within 3 days

(12)

of receipt statement/report from any political party. The status report should have links to the scanned copy of the concerned party's report/statements.

(iii) The last dates for filling of reports/statements by political parties are as under:

1. Contribution reports- 30th September every year or such date, as extended by CBDT, for filing Income Tax Return.
2. Annual Audited account- 31stOctober every year.
3. Statement of election expenditure- within 75 days of completion of Assembly election and 90 days of completion of Lok Sabha election.

(iv) In case of default in filling the reports/statements, it should be brought to the notice of the political parties concerned, by writing a letter to that effect and the letter should also be put on the website of CEO.

(v) A copy of the contribution report shall be forwarded to the Principal Chief Commissioner of Income Tax of the state concerned mentioning the date of submission of such report by the political party. The parties which have not submitted the contribution report in time shall be processed by the Income Tax Department, for denial of tax benefit in accordance with Section-29 C of the R.P. Act. 1951.

(vi) The contribution report shall also be forwarded to Ministry of Home Affairs, Government of India for scrutiny and action by that Ministry about any donation received from foreign sources, as defined under clause (j) of Section 2 of Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010.

Yours faithfully,
Sd/-
(MALAY MALLICK)
UNDER SECRETARY

Copy to:

Director (IT) to facilitate the proposed changes in the website of CEO's and ECI.

(13)

Annexure- F6

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 76/PPEMS/Transparency/2013

Dated: 19th November, 2014

To

1. The President/General Secretary
   of all political parties
2. The Treasurers of all Political Parties

Subject: Clarification of transparency guidelines for the political parties issued by Election Commission of India on 29.08.2014 - matter reg.

Madam/Sir,

Kindly refer to Commission's letter No. 76/PPEMS/Transparency/2013 dated 29.08.2014, wherein the Commission issued transparency guidelines for the political parties invoking Article 324 of the constitution. Representations have been received from a few parties raising doubt about the powers of the Commission and asking for clarifications on certain issues. After considering the representations, the following issues are hereby clarified:

1. Under Article 324 of the Constitution, the Commission has plenary powers and also sacred duty, to conduct free and fair elections in the country. Of late, the increasing use of Black money in election campaigns has been noticed and is causing serious concern all around. The use of black money in elections disturbs the level playing field and vitiates the purity of election process. Therefore, there was need to issue the transparency guidelines, in order to protect the purity of election process and for conduct of free and fair elections, as enshrined in the Constitution. There was legal vacuum in this area, which can be filled by the Election Commission of India as held by the Hon'ble Supreme Court in Mohinder Singh Gill vs CEC (AIR 1978 SC 851).

2. The guidelines have been framed after due consultation with all recognized political parties. The lawful instructions, thus issued by the Commission under Article 324, are binding on all political parties and their violations shall affect the transparency of election process which is the bedrock of a democracy.

3. The instruction to political parties to file Annual Audited Accounts with the Commission is essential for maintaining transparency in the functioning of political parties, which is an essential ingredient for conduct of free and fair election. The direction to maintain the name and address of the individuals, companies and entities making donations to the political parties is intended to ensure that no funds are received by the political parties from prohibited sources as stipulated in section 29B of the R.P. Act 1951. However, the Commission is alive to the practice of raising funds by political parties through hundi/bucket collection in public meetings/rallies, where it is not possible to record the name and address of the donors. Therefore, the Commission has exempted such collections from the ambit of

(14)

the above instruction. In case of all donations other than those raised through hundi/bucket collection in a public meeting/rally, the record of name and address of each donor has to be maintained by the political party, as is done by all other social/civil society/organizations.

4. The cash received by political parties has to be deposited in its bank accounts within a period of 10 working days excepting the amount required to defray its day-to-day expenses. It is clarified that the total amount of cash in hand of a registered political party for the purpose of defraying its day-to-day expenses shall not normally exceed the average monthly cash expenditure of the party during the last financial year.

5. All political parties are required to submit their election expenditure statement before the ECI within 75 days of assembly election or 90 days of Lok Sabha elections as stipulated by the Election Commission of India in pursuance of the order of the Hon. Supreme Court and it is thus required that the parties file their true and correct statement of their election expenses within the stipulated time limit. Since all the political parties and candidates are having bank accounts and also the banks have extended services to foster inclusiveness, all parties shall make payments in excess of Rs.20,000/-* to a person or entity on a single day by account payee cheque or draft or by account transfer excepting the payments, mentioned in para (IV) of the said Transparency Guidelines. This will help in curbing excessive flow of cash during elections and will bring in transparency in the election expenditure of the parties.

6. It has been the endeavour of the Commission to maintain level playing field for all political parties and all candidates during elections. In the interest of conduct of free and fair elections, all parties are required to follow the transparency guidelines issued by the Commission, and violation of lawful direction of the Commission may entail action, as envisaged under para 16A of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968.

Yours faithfully,

Sd/-

(Malay Mallick)

UNDER SECRETARY

*Note:- Please refer Annexure-E11 and E12.

(15)

रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल

अधिसूचना में क्रम सं0	क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल / मुख्यालय का पता	विधान सभा निर्वाचन–2017 में चुनाव लड़ा गया (हाँ / नहीं)	लोक सभा निर्वाचन–2019 में चुनाव लड़ा गया (हाँ / नहीं)	विधान सभा निर्वाचन–2022 में चुनाव लड़ा गया (हाँ / नहीं)
1	2	3	4	5	6
453	1.	भारत कौमी दल ग्राम -लाठ्ठरदेवा हूण, पो0 झबरेडा, जिला-हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	नहीं
466	2.	भारत परिवार पार्टी भारत ह्रदय आश्रम, मौ0 कड़च्छ ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407	नहीं	नहीं	नहीं
510	3.	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल बंसल गांव, पो. ऑ. - धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला - अल्मोडा (उत्तराखण्ड) ।	नहीं	नहीं	नहीं
536	4.	भारतीय जनक्रांति पार्टी 12/17, चक्खुवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
552	5.	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी 77/129, भगत सिहँ कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
585	6.	भारतीय सम्राट सुभाष सेना ग्राम - अजीतपुर, पो0 - कनखल,लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408	नहीं	नहीं	नहीं
597	7.	भारतीय शक्ति सेना शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादराबाद, हरिद्वार - 249 402 उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
620	8.	भारतीय अंत्योदय पार्टी 8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171	नहीं	नहीं	नहीं
646	9.	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी एकता विहार, लेन नं. -1,ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पी०ओ० -कण्डोली, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001 ।	नहीं	नहीं	नहीं
767	10.	भारतीय सर्वोदय पार्टी 152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।	हाँ	हाँ	नहीं
770	11.	भारतीय सेवक पार्टी उत्तराखण्ड ग्रमिण बैंक के नजदीक, बुग्गावाला (मेन मार्केट) हरिद्वार उत्तराखण्ड पिन–247662	नहीं	नहीं	नहीं
789	12.	भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी मकान न0 63 रामपुर रोड़ मानपुर उत्तर हल्द्वानी नैनीताल पिन–263139	नहीं	नहीं	नहीं
962	13.	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट शाही निवास चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं

977	14.	हमारी जनमंच पार्टी 1/12, नया चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	नहीं
1538	15.	मैदानी क्रान्ति दल मुख्यालय - मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।	नहीं	नहीं	नहीं
1783	16.	न्याय धर्मसभा पार्टी प्रगति विहार जगजीतपुर हरिद्वार पिन 24908	नहीं	नहीं	हाँ
1798	17.	पहाड़ी पार्टी ग्र0ततली बागी पट्टी सारज्यूला पो0 भगीरथपुरम विकास खण्ड चम्बा जिला टिहरी पिन 249145	नहीं	नहीं	नहीं
1829	18.	पीपुल्स पार्टी ए-23, सुभाष नगर, रूड़की, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड	हाँ	नहीं	नहीं
1865	19.	प्रगतिशील लोक मंच ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा, पो0 ओ0 - अर्जुनपुर (हल्द्वानी), जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड ।	नहीं	हाँ	नहीं
1890	20.	प्रजामंडल पार्टी बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गढवाल, उत्तराखण्ड - 246174	हाँ	नहीं	नहीं
1897	21.	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं
2017	22.	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।	हाँ	नहीं	हाँ
2059	23.	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी 62, सिविल लाईन्स , रूड़की, जनपद - हरिद्वार,उत्तराखण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
2081	24.	राष्ट्रीय जन सहाय दल 112, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	नहीं
2249	25.	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी 124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	नहीं	हाँ
2318	26.	सैनिक समाज पार्टी 317– शिवा डिस्पोजल कैम्प्लेक्स संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड़ चन्द्रभागा आर्दश ग्राम. ऋषिकेश पिन–249201	हाँ	नहीं	हाँ
2405	27.	सर्व विकास पार्टी गाँव - प्रतीत नगर, एन0 एच0 - 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205	हाँ	हाँ	नहीं
2527	28.	सुराज सेवा दल ग्राम - रामड़ी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं

2694	29.	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001	नहीं	नहीं	नहीं
2695	30.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।	हाँ	हाँ	हाँ
2696	31.	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रिटिक) 85/ 12 – बी, नाश विला रोड़, देहरादून – 248001, (उत्तराखंण्ड)।	हाँ	हाँ	हाँ
2697	32.	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला – चमोली, उत्तराखण्ड ।	हाँ	हाँ	हाँ
2698	33.	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी 13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोजेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।	नहीं	हाँ	नहीं
2699	34.	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा मकान नं0 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट–मोथरोंवाला, विकासखण्ड–रायपुर, जिला–देहरादून, (उत्तराखण्ड)	हाँ	नहीं	हाँ
2702	35.	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी 53 – के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंण्ड ।	नहीं	नहीं	नहीं
2693	36.	उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी 18– एफ, सेक्टर बी0 निकट सी0 ब्लॉक टाईप 2 नई टिहरी	नहीं	नहीं	हाँ
2692	37.	उत्तराखण्ड जनता पार्टी प्लाट न0–6 प्रकाश इनक्लेव, शिमला रोड़, सेवला कला, देहरादून उत्तराखण्ड–248001	नहीं	नहीं	हाँ
2877	38.	भारत एकता मिशन पार्टी 171/123, आराघर, देहरादून।	नहीं	नहीं	नहीं
11-03-2022	39.	राज्य सवराज पार्टी 931,इन्दरा नगर, देहरादून उत्तराखण्ड।	नहीं	नहीं	नहीं
2805	40.	जनता कैबिनेट पार्टी, 16/ A (16/1) , लेटान रोड़ सुभाष रोड देहरादून न्यू नगर निगम, न0 184/4, पिन 248001 उत्तराखण्ड	नहीं	नहीं	नहीं
2875	41.	भारतीय राष्ट्रीय एकता दल, 10/10, मोहल्ला कैटवाड़ा, निय अम्बेडकर चौक, ज्वालापुर जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड 249407	नहीं	नहीं	नहीं

नोटः– 1–विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2017 में निर्वाचन लड़ने वाले दलों की संख्या–14
2–लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में निर्वाचन लड़ने वाले दलों की संख्या–07
3–विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 में निर्वाचन लड़ने वाले दलों की संख्या–10

Speed Post/E-mail

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi- 110001

File No.56/pol.parties/2021/PPS-III Date: 25th May, 2022

To,

The Chief Electoral Officers,
All States/UTs

Subject:- **Commission's Order dated 25/05/2022 regarding Enforcement of compliances in r/o Registered Unrecognized Political Parties (RUPPs)- reg.**

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith Commission's Order dated 25/05/2022 regarding Enforcement of compliances in r/o Registered Unrecognized Political Parties (RUPPs) (copy enclosed) along with list of registered unrecognized political parties pertaining to your State/UT with the direction to put this order and the list of RUPP on your websites for compliance and for affording an opportunity to anyone aggrieved by above action. In this regard your attention is invited to para 8.1 and 8.2 of the aforementioned order.

Yours faithfully,

(Manish Kumar)
UNDER SECRETARY
Ph. 23052008, Ext. 487

Enclosure: Annexed copy of Commission's Order dated 25.05.2022 and segregated list of political parties.

URGENT
Put-up file
S.O(R)

26/5/2022
ACEO

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 56/pol.parties/2021/PPS-III (Part)/Conf-2022 Dated: 25th May, 2022

ORDER

1. India is a multi-party democracy and Election Commission facilitates and regulates registration of political parties u/s 29A of the Representation of the People Act, 1951. Consequent upon registration, a political party gets several entitlements, inter-alia, party can collect donations, which is fully **exempted from income tax.** In elections, they are entitled for privileges of common symbol, preference over independents on ballot, vehicles, star campaigners etc.

2. **There are 2796** Registered Unrecognised Political Parties **(RUPP)** as in September 2021 (https://eci.gov.in/files/file/13711-list-of-political-parties-symbol-main-notification-dated23092021/) There were 694 RUPP in 2001. In two decades, the growth in registration of parties **has been ~300%.** Evidence suggests that there is a spurt in registration before general election of Lok Sabha/Vidhan Sabha.

3. Every RUPP so registered is required to comply with certain rules / instructions and directions, as conditions of registration and it also gives a categorical undertaking to this effect in its application. Relying on the same ECI grants registration. These, inter alia, include:

   i. **Section 29 C** of RP Act 1951 requires a RUPP to furnish a **contribution report** as prescribed in Form 24 A under Rule 85 B of Conduct of Election Rules 1961. Such contributions are exempted from the provisions of Income Tax as an incentive to the parties for strengthening the electoral democracy. Form 24 A requires the signatories (Treasurer/Authorised person) of a party to inter- alia provide details such as-

      - Address of the headquarters of the Political Party including any changes;
      - Permanent Account Number and Income-tax Ward/Circle where return of the political party is filed;
      - Contributions received in excess of Rs.20,000 including particulars of donors;
      - in case of payment by cheque/demand draft, name of the bank and branch of the bank;

DD

- in case the contributor is a company, whether the conditions laid down under section 293A of the Companies Act, 1956 (as amended) have been complied with.

ii. The political parties are mandated to furnish **Audited Annual Statements**, flowing from ECI's **transparency guidelines** dated 29/08/2014 as amended, inter-alia, requiring the party to adhere to the following:

" (i) Provision (a) to Section 13A of Income Tax Act 1961, inter-alia, provides that political party shall keep and maintain such books of accounts and other documents as would enable proper deduction of its income there from. Accordingly, it is required that

(a) the treasurer of the political party or such person as authorized by the party, besides ensuring maintenance of the accounts at all State and lower levels, shall maintain consolidated accounts at the central party Head Quarters as required under the aforesaid provision.

(b) the accounts so maintained by him/her shall conform to the guidance note on Accounting and Auditing of political parties, issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), and

(c) the Annual Accounts shall be audited and certified by the qualified practicing Chartered Accountants."

The Commission in its instructions dated 19/11/2014 further clarified,

"The instruction to political parties to file Annual Audited Accounts with the Commission is essential for maintaining transparency in the functioning of political parties, which is an essential ingredient for conduct of free and fair election. The direction to maintain the name and address of the individuals, companies and entities making donations to the political parties is intended to ensure that no funds are received by the political parties from prohibited sources as stipulated in section 29B of the R.P. Act 1951."

While emphasizing upon transparency in election funds, following has been held by Hon'ble Supreme Court in **People's Union for Civil Liberties (PUCL) and Anr. v. Union of India and Anr. [(2003) 4 SCC 399]** : -

"... Transparency in the context of election means both the sources of finance as well as their utilization as are listed out in an audited statement. If the candidates are required to list the sources of their income, this can be checked back by the Income Tax Authorities. The (Law) *Commission recommends that the political parties as well as individual candidates be made subject to a proper statutory audit of the amounts they spend. These accounts should be monitored through a system of checking and cross-checking through the income tax returns filed by the candidates, parties and their well-wishers..."*

Furthermore, echoing the same. Delhi High Court in **Commissioner of Income Tax Delhi- Vs. Indian National Congress (I)**/ All India Congress Committee ITA 145 and 180/2001 has held that –

> *"Considering that political parties are an essential part of our* ***democracy and are dealing in large sums of public money, much of which is unaccounted, the proper auditing of the accounts of the political parties is both imperative critical to the conduct of free and fair elections.*** *The above recommendations of the 255th LCI report should receive serious and urgent attention at the hands of the executive and the legislature if money power should not be allowed to distort the conduct of free and fair elections. This will in turn infuse transparency and accountability into the functioning of the political parties thereby strengthening and deepening democracy.".*

Hon'ble Supreme Court in **Common Cause vs UoI & Others (AIR 1996 SC 3081) has held,**

".... *16. "It is obvious that there has been total inaction on the part of the Government to enforce the provisions of the Income Tax Act relating to the filing of a return of income by a political party. The provisions of Section 13-A of the Income Tax Act read with Section 293-A of the Companies Act clearly indicate the legislative scheme the object of which is to ensure that there is transparency in the process of fund-collecting and incurring expenditure by the political parties.* ***The requirement of maintaining audited accounts by the political parties is mandatory and has to be strictly enforced****. It was obligatory for the income tax authorities to have strictly enforced the statutory provisions of the Income Tax Act."*

> ***The political parties, therefore, are under a statutory obligation to furnish a return of income for each assessment year.*** *To be eligible for exemption from income-tax they have to maintain audited accounts and comply with the other conditions envisaged under Section 13A of the Income-tax Act. ..."*

"... *5. A political party which is not maintaining, audited and authenticated, accounts and has not filed the return of income for the relevant period,* ***cannot, ordinarily, be permitted to say that it has incurred or authorised expenditure*** *in connection with the election of its candidates in terms of Explanation 1 to Section 77 of the R.P. Act.* (1951) ..."

[emphasis supplied]

iii. Every Political Party, for being registered, as a condition precedent prescribed by ECI under its power under section 29 A (6), undertakes to include in its constitution that it must contest an election conducted by the Election Commission within 5 years of its registration.

iv. Sec 29 A (9) mandates every political party to communicate any change in its name, head office, office bearers, address or in any other material matters to the commission without delay.

v. Further, upon participation in an election political parties are required to furnish their **election expenditure statement** within 75 days, in case of Assembly elections, and within 90 days, in case of Lok Sabha elections.

4. The above create **'birth' conditions, which** are a combination of mandated and self-acknowledged provisions by the respective party. These conditions assume a legal and moral obligation that all registered parties carry. They also provide a matrix for both self-regulation by a political party itself and, independently by the ECI.

5. **The Commission places these reports in public domain by way of placing it on its website**, and thus informs the citizens of the country about the affairs of the political parties, who are one of the most important stake holders in the democratic process.

6. **The Commission has noted with serious concern that out of the total 2796 RUPPs, a large number** is neither taking part in electoral process nor adhering to the one or many of the above requirements including submission of Contribution Reports; Annual Audit Statement; Election Expenditure Statement; and Contesting Elections, etc which is not only violative of statutory requirements and extant guidelines in the following manner but also **defeats the purpose of clean electoral ecosystem:**

6.1 **87 such RUPPs** are not found in existence at their notified addresses as per the field verification reports received from the concerned Chief Electoral Officers.

6.2 **Non-Contesting of Elections**. In General Elections 2019, out of total 2354 RUPPs parties at that time, only 623 RUPPs contested elections (details available at https://eci.gov.in/files/category/1551-general-election-2019-including-vellore-pc/). **At least ~70% registered unrecognised parties did not contest elections. Possibility of** a large number of such parties occupying the available pre- election political space by taking benefits of admissible entitlements without contesting elections, cannot be ruled out. This also tends to crowd out the political parties actually contesting elections and also creating confusing situation for the voters.

6.3 **Non-filing of Contribution Report by many RUPP** at all or in time, hence violating statutory provisions. Reported details are as follows:

Year	Number of RUPP	Number of RUPPs which have filed on or before due date.	Number of RUPPs which have filed after due date.	Number of RUPPs which have NOT filed their contribution report. (in%)
2017	1983	57	79	**1847 (93%)**
2018	2143	65	81	**1997 (93%)**
2019	2354*	60	120	**2174 (92%)**

* (https://eci.gov.in/files/file/9787-amendment-notificaiton-list-of-parties-and-symbols-english-dated-01042019/

6.4 Non filing of annual audit accounts by many RUPP at all or in time, hence violating ECI's instructions. Reported details are as follows:

Year	Number of RUPP	Number of RUPPs which have filed **on or before due date.**	Number of RUPPs which have filed **after due date.**	**Number of RUPPs which have NOT yet filed,**
2017	1983	117	111	**1755**
2018	2143	138	115	**1890**
2019	2354*	98	200	**2056**

* as above

6.5 The reported figures of non-filing of Election Expenditure Statement ,required to be filed within 75 days of completion of General assembly elections, in the five states where elections to Legislative Assembly were recently held. , are as following :

State	No. of RUPPs participated & with HQ in the election going state*	No. of RUPPs **submitted** Election Expenditure Statement	RUPPs that have **not submitted** Election Expenditure Statement
Assam	7	Nil	7
West Bengal	15	4	11
Tamil Nadu	75	10	65
Kerala	17	1	16
Puducherry	1	Nil	1

Total	115	15	100

6.6 Further, there have been reports about a few RUPPs about their indulgence in serious financial impropriety such as incriminating documents related to bogus donation receipts, formation of shell entities, bogus and non-genuine purchases, facilitating accommodation entries, etc. It amounts to fraudulent use of privileges and public trust available to them. This necessitates an urgent need to crosscheck the compliance adherence, and legality of the activities of such parties.

6.7 As per data obtained **from CBDT,** 199 RUPPs claimed Rs 445 Cr exemption in 2018-19. In 2019-20, 219 such parties claimed **Rs 608 Cr exemption from Income Tax**. 66 RUPPs, which have claimed **Rs 385 Cr exemptions** in 2019-20, have not submitted contribution reports in Form 24A as mandated under section 29C of the Act. A few RUPPs have claimed **income tax exemption even to the tune of Rs 100 to150 crores** each without complying with statutory compliances, including submission of contribution report in Form 24 A under Section 29 C of the R P Act 1951.

7. **The Commission is cognizant that compliances of the birth conditions,** which are a combination of mandated and self-acknowledged provisions, are sine qua non for maintaining financial discipline, propriety, public accountability, transparency. The compliances work as the building blocks of a transparency mechanism for informing the voters of the affairs of the political parties necessary for making informed choices. In the absence of required compliances, the electorate and the Election Commission get blindsided. Further all these stated regulatory requirements have direct nexus with Commission's constitutional mandate of conducting free, fair and transparent elections.SC in ***Union Of India v. Association for Democratic Reforms and Ors, AIR 2002 SC 2112)*** has held that:

> *"4. In a democracy, **the electoral process has a strategic role**. The little man of this country would have basic elementary right to know full particulars of a candidate who is to represent him in Parliament where laws to bind his liberty and property may be enacted.*
>
> [emphasis supplied]

8. In view of the foregoing, immediate corrective measures are warranted in larger public interest as well as for the purity of electoral democracy. **Therefore, the Commission, in discharge of its mandate** of ensuring just, free, fair & transparent electoral process hereby directs that:

(1) **There are 87 RUPPs**, whose address of communication, was statutorily required as registration requirement under section 29A(4). Any change in address was required to be communicated to the ECI under section 29A(9), which they have not complied. These RUPPs have been found to be non-existent after a physical verification carried out by the respective Chief Electoral Officers. The names of such non existent RUPPs shall be deleted from the list

of register of unrecognized registered political parties. Any party aggrieved from this, may approach the concerned Chief Electoral Officer/ Election Commission within 30 days of the issue of this direction along with all evidences of existence, other legal and regulatory compliances including year wise annual audited accounts, contribution report, expenditure report, updation of office bearers including authorized signatories for financial transactions (including bank account). The segregated list of such RUPPs shall be sent to respective CEOs and CBDT for requisite action under extant legal framework.

(2) **87 such RUPPs**, as in para 8.1 above, in absence of ensuring remedial measures listed above, render themselves liable to be not entitled to have benefits under the Symbols Order, 1968, including allocation of common symbol.

(3) As in para 6.6 above, 3 RUPPs which have been reported, prima facie to be involved in serious financial impropriety such as incriminating documents related to bogus donation receipts, formation of shell entities, bogus and non-genuine purchases, facilitating accommodation entries, etc., shall be proceeded against under the extant legal/regulatory regime including entitlement to avail the benefits of Symbols Order, 1968. A reference shall be sent to the Department of Revenue, who have reported misuse, for taking all necessary legal and criminal actions against 3 RUPPs, as appropriate under the extant legal framework.

(4) As in para 6.7 above, it has been reported that income tax exemptions have been taken to the tune of Rs 445 Cr in 2018-19 by 199 RUPPs and **Rs 608 cr** in 2019-20 by 219 RUPPs . Of these 66 RUPPS have claimed income tax exemption without submitting contribution reports in Form 24A as mandated under section 29C of the Act.

Section 29 C of the RP Act, specify that:

(3) The report for a financial year under sub-section (1) shall be submitted by the treasurer of a political party or any other person authorised by the political party in this behalf before the due date for furnishing a return of its income of that financial year under section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) to the Election Commission.

(4) Where the treasurer of any political party or any other person authorised by the political party in this behalf fails to submit a report under sub-section (3), then, notwithstanding anything contained in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), such political party shall not be entitled to any tax relief under that Act.]

In view of the fact that there are 2174 RUPPs, which have not submitted contribution reports, the list shall be sent to the Department of Revenue for taking all consequential action as per the RP Act 1951 read with the relevant provisions of the Income Tax Act, 1961 and other statutory/regulatory regime including not granting exemption / withdrawing exemption, if already granted/ examining liability of wrongly claiming exemption as the case may be.

(5) **2056 RUPPs**, which have failed to furnish Annual Audit Account of the concerned financial year, are indicative of gaps in vital financial information including bank account, PAN, authorized signatories pertaining to those RUPPs, statement of assets and liabilities, contributions received, details of donors, expenditure, etc. . Therefore, CEOs shall put the list of such RUPPS on their respective websites and afford an opportunity to such RUPPs to comply with extant legal and regulatory regime within 30 days. Non-compliance may make such RUPPs not entitled to have benefits under the Symbols Order, 1968, including allocation of common symbol.

(6) **100 RUPPs, which** have failed to furnish Election Expenditure Statements after the contest of election(s), have violated the directions of Election Commission. They may approach concerned Chief Electoral Officer with full facts within 30 days of the issue of this direction for remedial action, if any, to avoid any consequential action.

(7) All Chief Electoral Officers shall put this order on their websites for compliance and for affording an opportunity to anyone aggrieved by above action. Any RUPP aggrieved by any action under point 8.1 to 8.6 may approach concerned Chief Electoral Officer with full facts within 30 days of the issue of this direction with all evidences inter-alia including proof of existence, other legal and regulatory compliances made till now such as submission of year wise annual audited accounts, contribution report, expenditure report , if any, updation of office bearers including authorized signatories for financial transactions (including bank account) and operations under the Symbols Order 1968, etc.

By Order

(K.N.Bhar)
Sr Principal Secretary

27

(3) यदि पीठासीन आफिसर रुग्णता या अन्य अपरिवर्जनीय हेतुक के कारण मतदान केन्द्र से स्वयं अनुपस्थित रहने के लिए बाध्य हो जाए तो उसके कृत्यों का पालन ऐसे मतदान आफिसर द्वारा किया जाएगा जिसे [1][जिला निर्वाचन आफिसर] ने किसी ऐसी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे कृत्यों के पालन के लिए पहले से ही प्राधिकृत किया है ।

(4) इस अधिनियम में पीठासीन आफिसर के प्रति निर्देशों के अन्तर्गत, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, उस किसी कृत्य का पालन करने वाला कोई व्यक्ति आता है जिस कृत्य का पालन करने के लिए वह, यथास्थिति, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्राधिकृत है, यह समझा जाएगा ।

[2]* * * * * * *

27. पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य--मतदान केन्द्र में व्यवस्था बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना कि मतदान ऋजुता से हो मतदान केन्द्र में के पीठासीन आफिसर का साधारण कर्तव्य होगा ।

28. मतदान आफिसर के कर्तव्य---मतदान केन्द्र के मतदान आफिसरों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे केन्द्र के पीठासीन आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता करें ।

[3][**28क. रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, आदि को निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझना**---किसी निर्वाचन के संचालन के लिए रिटर्निंग आफिसर, सहायक रिटर्निंग आफिसर, पीठासीन आफिसर, मतदान आफिसर और इस भाग के अधीन नियुक्त कोई अन्य आफिसर, और किसी राज्य सरकार द्वारा तत्समय पदाभिहित कोई पुलिस आफिसर, उस अवधि के लिए, जो ऐसे निर्वाचन की अपेक्षा करने वाली अधिसूचना की तारीख से प्रारंभ होती है और ऐसे निर्वाचन के परिणामों के घोषित किए जाने की तारीख को समाप्त होती है, निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे और तदनुसार ऐसे आफिसर उस अवधि के दौरान निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन होंगे ।]

29. कतिपय निर्वाचनों की दशा में विशेष उपबंध---(1) राज्य सभा में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन के लिए या राज्य की विधान परिषद् में के स्थान या स्थानों को भरने के लिए राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन के लिए [4]*** रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन आयोग के पूर्वानुमोदन से वह स्थान नियत करेगा जहां कि ऐसे निर्वाचन के लिए मतदान होगा और ऐसे नियत स्थान की ऐसी रीति में अधिसूचित करेगा जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे ।

(2) रिटर्निंग आफिसर ऐसे नियत स्थान में ऐसे निर्वाचन में पीठासीन होगा और अपनी सहायता के लिए ऐसा या ऐसे मतदान आफिसर नियुक्त करेगा जैसे वह आवश्यक समझे, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो निर्वाचन में या निर्वाचन की बाबत अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित किया गया है या अन्यथा उसके लिए काम करता रहा है ।

[5][**भाग 4क**

राजनैतिक दलों का रजिस्ट्रीकरण

29क. संगमों और निकायों का राजनैतिक दलों के रूप में आयोग के पास रजिस्ट्रीकरण---(1) भारत के व्यष्टिक नागरिकों का कोई संगम या निकाय, जो स्वयं को राजनैतिक दल कहता है और जो इस भाग के उपबंधों का लाभ उठाना चाहता है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, राजनैतिक दल के रूप में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने के लिए निर्वाचन आयोग को आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक आवेदन,---

(क) यदि संगम या निकाय लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1989 का 1) के प्रारंभ पर विद्यमान है तो ऐसे प्रारंभ के ठीक आगामी साठ दिन के भीतर किया जाएगा ;

---

1. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 26 द्वारा (14-12-1966 से) "रिटर्निंग आफिसर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. 1966 के अधिनियम सं0 47 की धारा 12 द्वारा (14-12-1966 से) अन्तःस्थापित और 2004 के अधिनियम सं0 2 की धारा 3 द्वारा (29-10-2003 से) लोप किया गया ।
3. 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 5 द्वारा (15-3-1989 से) अन्तःस्थापित ।
4. 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 13 द्वारा (28-8-1956 से) "(प्राथमिक निर्वाचन से भिन्न)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया गया ।
5. 1989 के अधिनियम सं0 1 की धारा 6 द्वारा (15-6-1989 से) अन्तःस्थापित ।

(*3*) If the presiding officer, owing to illness or other unavoidable cause, is obliged to absent himself from the polling station, his functions shall be performed by such polling officer as has been previously authorised by the [1][district election officer] to perform such functions during any such absence.

(*4*) References in this Act to the presiding officer shall, unless the context otherwise requires, be deemed to include any person performing any function which he is authorised to perform under sub-section (*2*) or sub-section (*3*), as the case may be.

[2]* * * * *

27. General duty of the presiding officer.—It shall be the general duty of the presiding officer at a polling station to keep order thereat and to see that the poll is fairly taken.

28. Duties of a polling officer.—It shall be the duty of the polling officers at a polling station to assist the presiding officer for such station in the performance of his functions.

[3][**28A. Returning officer, presiding officer, etc., deemed to be on deputation to Election Commission.**—The returning officer, assistant returning officer, presiding officer, polling officer, and any other officer appointed under this Part, and any police officer designated for the time being by the State Government, for the conduct of any election shall be deemed to be on deputation to the Election Commission for the period commencing on and from the date of the notification calling for such election and ending with the date of declaration of the results of such election and accordingly, such officers shall, during that period, be subject to the control, superintendence and discipline of the Election Commission.]

29. Special provisions in the case of certain elections.—(*1*) The returning officer for an election [4]* * * to fill a seat or seats in the Council of States or for an election by the members of the Legislative Assembly of a State to fill a seat or seats in the Legislative Council of the State shall, with the previous approval of the Election Commission, fix the place at which the poll will be taken for such election and shall notify the place so fixed in such manner as the Election Commission may direct.

(*2*) The returning officer shall preside over such election at the place so fixed and shall appoint such polling officer or officers to assist him as he thinks necessary but he shall not appoint any person who has been employed by or on behalf of, or has been otherwise working for, a candidate in or about the election.

[5][PART IVA

REGISTRATION OF POLITICAL PARTIES

29A. Registration with the Election Commission of associations and bodies as political parties.— (*1*) Any association or body of individual citizens of India calling itself a political party and intending to avail itself of the provisions of this Part shall make an application to the Election Commission for its registration as a political party for the purposes of this Act.

(*2*) Every such application shall be made,—

(*a*) if the association or body is in existence at the commencement of the Representation of the People (Amendment) Act, 1988 (1 of 1989), within sixty days next following such commencement;

---

1. Subs. by Act 47 of 1966, s. 26, for "returning officer" (w.e.f. 14 -12-1966.)
2. Sub-section (*5*) ins. by s. 12, *ibid.* (w.e.f. 14-12-1966) and omitted by Act 2 of 2004, s.3 (w.e.f. 29-10-2003).
3. Ins. by Act 1 of 1989, s. 5 (w.e.f. 15-3-1989.)
4. The words and brackets "(other than a primary election)" omitted by Act 27 of 1956, s. 13 (w.e.f. 28-8-1956).
5. Ins. by Act 1 of 1989, s. 6 (w.e.f. 15-6-1989).

(ख) यदि संगम या निकाय ऐसे प्रारंभ के पश्चात् बनाया जाता है तो उसके बनाए जाने की तारीख के ठीक आगामी तीस दिन के भीतर किया जाएगा ।

(3) उपधारा 1 के अधीन प्रत्येक आवेदन पर संगम या निकाय के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के (चाहे ऐसा मुख्य कार्यपालक अधिकारी सचिव के रूप में जाना जाता है या किसी अन्य पदाभिधान से जाना जाता है) हस्ताक्षर होंगे और वह आयोग के सचिव को पेश किया जाएगा या ऐसे सचिव को रजिस्ट्री डाक से भेजा जाएगा ।

(4) ऐसे प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :---

(क) संगम या निकाय का नाम ;

(ख) वह राज्य जिसमें उसका प्रधान कार्यालय स्थित है ;

(ग) वह पता जिस पर उसके लिए आशयित पत्र और अन्य संसूचनाएं भेजी जाएं ;

(घ) उसके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के नाम ;

(ङ) उसके सदस्यों की संख्या और यदि उसके सदस्यों के प्रवर्ग हैं तो प्रत्येक प्रवर्ग की संख्या ;

(च) क्या उसके कोई स्थानीय एकक हैं, यदि हैं, तो किन स्तरों पर हैं ;

(छ) क्या संसद् के या किसी राज्य विधान-मंडल के किसी सदन में किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों द्वारा उसका प्रतिनिधित्व किया जाता है ; यदि किया जाता है तो ऐसे सदस्य या सदस्यों की संख्या ।

(5) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ संगम या निकाय के, ज्ञापन या नियमों और विनियमों की चाहे वह जिस नाम से ज्ञात हो, एक प्रति होगी और ऐसे ज्ञापन या नियमों और विनियमों में यह विनिर्दिष्ट उपबंध होगा कि वह संगम या निकाय विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति तथा समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा और भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा ।

(6) आयोग संगम या निकाय से ऐसी अन्य विशिष्टियां मंगा सकेगा जैसी वह ठीक समझे ।

(7) आयोग अपने कब्जे में की यथापूर्वोक्त सभी विशिष्टियों और कोई अन्य आवश्यक और सुसंगत बातों पर विचार करने के पश्चात् और संगम या निकाय के प्रतिनिधियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् या तो उस संगम या निकाय को इस भाग के प्रयोजनों के लिए राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत करने का, या जो इस प्रकार रजिस्ट्रीकृत न करने का, विनिश्चय करेगा ; और आयोग अपना विनिश्चय ऐसे संगम या निकाय को संसूचित करेगा :

परंतु कोई संगम या निकाय इस उपधारा के अधीन राजनैतिक दल के रूप में तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे संगम या निकाय का ज्ञापन या नियम और विनियम उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुरूप नहीं हैं ।

(8) आयोग का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(9) किसी संगम या निकाय के यथापूर्वोक्त राजनैतिक दल के रूप में रजिस्ट्रीकृत किए जाने के पश्चात् उसके नाम, प्रधान कार्यालय, पदाधिकारियों, पते या किन्हीं अन्य तात्विक विषयों में कोई तब्दीली आयोग को अविलंब संसूचित की जाएगी ।]

[1][29ख. **राजनैतिक दलों का अभिदाय स्वीकार करने का हकदार होना**---कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राजनैतिक दल, सरकारी कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा उसे स्वेच्छया प्रस्थापित अभिदाय की कोई भी रकम स्वीकार कर सकेगा :

परन्तु कोई भी राजनैतिक दल विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 49) की धारा 2 के खंड (ङ) के अधीन परिभाषित किसी विदेशी स्रोत से कोई अभिदाय स्वीकार करने का पात्र नही होगा ।

---

1. 2003 के अधिनियम सं0 46 की धारा 2 द्वारा (11-9-2003 से) अंतःस्थापित ।

30

(*b*) if the association or body is formed after such commencement, within thirty days next following the date of its formation.

(*3*) Every application under sub-section (*1*) shall be signed by the chief executive officer of the association or body (whether such chief executive officer is known as Secretary or by any other designation) and presented to the Secretary to the Commission or sent to such Secretary by registered post.

(*4*) Every such application shall contain the following particulars, namely:—

(*a*) the name of the association or body;

(*b*) the State in which its head office is situate;

(*c*) the address to which letters and other communications meant for it should be sent;

(*d*) the names of its president, secretary, treasurer and other office-bearers;

(*e*) the numerical strength of its members, and if there are categories of its members, the numerical strength in each category;

(*f*) whether it has any local units; if so, at what levels;

(*g*) whether it is represented by any member or members in either House of Parliament or of any State Legislature; if so, the number of such member or members.

(*5*) The application under sub-section (*1*) shall be accompanied by a copy of the memorandum or rules and regulations of the association or body, by whatever name called, and such memorandum or rules and regulations shall contain a specific provision that the association or body shall bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and to the principles of socialism, secularism and democracy, and would uphold the sovereignty, unity and integrity of India.

(*6*) The Commission may call for such other particulars as it may deem fit from the association or body.

(*7*) After considering all the particulars as aforesaid in its possession and any other necessary and relevant factors and after giving the representatives of the association or body reasonable opportunity of being heard, the Commission shall decide either to register the association or body as a political party for the purposes of this Part, or not so to register it; and the Commission shall communicate its decision to the association or body:

Provided that no association or body shall be registered as a political party under this sub-section unless the memorandum or rules and regulations of such association or body conform to the provisions of sub-section (*5*).

(*8*) The decision of the Commission shall be final.

(*9*) After an association or body has been registered as a political party as aforesaid, any change in its name, head office, office-bearers, address or in any other material matters shall be communicated to the Commission without delay.]

[1][**29B. Political parties entitled to accept contribution.**—Subject to the provisions of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), every political party may accept any amount of contribution voluntarily offered to it by any person or company other than a Government company:

Provided that no political party shall be eligible to accept any contribution from any foreign source defined under clause (*e*) of section 2 of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 1976 (49 of 1976).

1. Ins. by Act 46 of 2003, s. 2 (w.e.f. 11-9-2003).

स्पष्टीकरण--इस धारा और धारा 29ग के प्रयोजनों के लिए,---

(क) "कंपनी" से धारा 3 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ;

(ख) "सरकारी कंपनी" से धारा 617 के अर्थांतर्गत कोई कंपनी अभिप्रेत है; और

(ग) "अभिदाय" का वही अर्थ है जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 293क में है और इसके अंतर्गत किसी राजनैतिक दल को किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्थापित कोई संदान या अभिदान भी है; और

(घ) "व्यक्ति" का वही अर्थ है जो आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (31) में है किन्तु इसके अंतर्गत सरकारी कंपनी, स्थानीय प्राधिकारी और सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति नहीं है ।

29ग. राजनैतिक दलों द्वारा प्राप्त संदान की घोषणा---(1) किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, निम्नलिखित के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा, अर्थात्:–

(क) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक का अभिदाय ;

(ख) ऐसे राजनैतिक दल द्वारा उस वित्तीय वर्ष में सरकारी कंपनियों से भिन्न कंपनियों से प्राप्त बीस हजार रुपए से अधिक अभिदाय :

[1][परन्तु इस उपधारा में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी निर्वाचन बंधपत्र द्वारा प्राप्त अभिदायों को लागू नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण–इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "निर्वाचन बंधपत्र" से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 31 की उपधारा (3) के स्पष्टीकरण में निर्दिष्ट कोई बंधपत्र अभिप्रेत है ।]

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट ऐसे प्ररूप में होगी जो विहित किया जाए ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्ट, किसी राजनैतिक दल के कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 139 के अधीन उस वित्तीय वर्ष की उसकी आय की विवरणी देने के लिए नियत तारीख से पूर्व, निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) जहां किसी राजनैतिक दल का कोषाध्यक्ष या उक्त राजनैतिक दल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उपधारा (3) के अधीन कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां, ऐसा राजनैतिक दल, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) में किसी बात के होते हुए भी, उस अधिनियम के अधीन किसी कर राहत का हकदार नहीं होगा ।]

भाग 5

निर्वाचनों का संचालन

अध्याय 1–अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

[2][**30. नामनिर्देशनों, आदि के लिए तारीखें नियत करना**---जैसे ही सदस्य या सदस्यों को निर्वाचित करने के लिए निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली अधिसूचना निकाली जाए वैसे ही निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा--

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अंतिम तारीख जो प्रथम वर्णित अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् वाले [3][सातवें दिन] की होगी या यदि वह दिन लोक अवकाश दिन है तो निकटतम उत्तरवर्ती ऐसे दिन की होगी जो लोक अवकाश दिन नहीं है ;

---

1. 2017 के अधिनियम सं0 7 की धारा 137 द्वारा (1-4-2017 से) अंतःस्थापित ।
2. 1956 के अधिनियम सं0 27 की धारा 14 द्वारा धारा 30 के स्थान पर (28-8-1956 से) प्रतिस्थापित ।
3. 1961 के अधिनियम सं0 40 की धारा 7 द्वारा (20-9-1961 से) "दसवें दिन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Explanation.—For the purposes of this section and section 29C,—

(*a*) "company" means a company as defined in section 3;

(*b*) "Government company" means a company within the meaning of section 617; and

(*c*) "contribution" has the meaning assigned to it under section 293A,

of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes any donation or subscription offered by any person to a political party; and

(*d*) "person" has the meaning assigned to it under clause (*31*) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), but does not include Government company, local authority and every artificial juridical person wholly or partially funded by the Government.

29C. Declaration of donation received by the political parties.—(*1*) The treasurer of a political party or any other person authorised by the political party in this behalf shall, in each financial year, prepare a report in respect of the following, namely:—

(*a*) the contribution in excess of twenty thousand rupees received by such political party from any person in that financial year;

(*b*) the contribution in excess of twenty thousand rupees received by such political party from companies other than Government companies in that financial year.

[1][Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to the contributions received by way of an electoral bond.

Explanation.—For the purposes of this sub-section, "electoral bond" means a bond referred to in the Explanation to sub-section (3) of section 31 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (1934 of 2)].

(*2*) The report under sub-section (*1*) shall be in such form as may be prescribed.

(*3*) The report for a financial year under sub-section (*1*) shall be submitted by the treasurer of a political party or any other person authorised by the political party in this behalf before the due date for furnishing a return of its income of that financial year under section 139 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), to the Election Commission.

(*4*) Where the treasurer of any political party or any other person authorised by the political party in this behalf fails to submit a report under sub-section (*3*) then, notwithstanding anything contained in the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), such political party shall not be entitled to any tax relief under that Act.]

PART V

CONDUCT OF ELECTIONS

CHAPTER I.—*Nomination of Candidates*

[2][**30. Appointment of dates for nominations, etc.**—As soon as the notification calling upon a constituency to elect a member or members is issued, the Election Commission shall, by notification in the Official Gazette, appoint —

(*a*) the last date for making nominations, which shall be the [3][seventh day] after the date of publication of the first-mentioned notification or, if that day is a public holiday, the next succeeding day which is not a public holiday;

1. Ins. by Act 7 of 2017, s. 137 (w.e.f. 1-4-2017).
2. Subs. by Act 27 of 1956, s. 14, for s. 30 (w.e.f. 28-8-1956).
3. Subs. by Act 40 of 1961, s. 7, for "tenth day" (w.e.f. 20-9-1961).